ShodhSamajik: Journal of Social Studies
July-September 2026 3(2)
https://shodhsamajik.com/

Original Article

FACTORS INFLUENCING THE VOTING BEHAVIOR OF WOMEN IN BIHAR: A STUDY

बिहार में महिलाओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक : एक अध्ययन

Aditya Raj [1*], **Dr. Md. Jawed Anwar** [2]
[1] Research Scholar, University Department of Political Science, Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga, Bihar, India
[2] Research Supervisor and Assistant Professor, Department of Political Science Samastipur College, Samastipur, Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga, Bihar, India

ABSTRACT

English: The growing political participation of women in Indian democracy has rendered the electoral process more inclusive and robust. In particular, the significant rise in the voter turnout of women in Bihar over the last decade has made the study of their voting behavior—and the factors influencing it—highly important. This study aims to analyze the social, economic, political, educational, and institutional factors that influence women's voting behavior in Bihar. To achieve this, a descriptive and analytical research methodology has been adopted, utilizing various secondary sources such as Election Commission data, census records, government reports, national surveys, and published research literature. The analysis reveals that women's voting behavior is no longer confined merely to caste, religion, or familial influence; rather, factors such as education, political awareness, government welfare schemes, media, local development, women's empowerment, and the credibility of candidates significantly shape their voting decisions. In conclusion, women in Bihar are emerging as an independent and decisive voting bloc, thereby strengthening both democratic accountability and representation. The study emphasizes the need to promote women's political literacy, digital awareness, leadership development, and women-centric democratic policies to make Indian democracy more participatory, inclusive, and accountable.

Hindi: भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी ने निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक समावेशी एवं सशक्त बनाया है। विशेषतः बिहार में पिछले एक दशक के दौरान महिला मतदाताओं की मतदान दर में उल्लेखनीय वृद्धि ने उनके मतदान व्यवहार तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य बिहार में महिलाओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक एवं संस्थागत कारकों का विश्लेषण करना है। इसके लिए निर्वाचन आयोग के आँकड़ों, जनगणना, सरकारी प्रतिवेदनों, राष्ट्रीय सर्वेक्षणों तथा प्रकाशित शोध साहित्य सहित विभिन्न द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करते हुए वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति अपनाई गई है। विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं का मतदान व्यवहार अब केवल जाति, धर्म अथवा पारिवारिक प्रभाव तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता, सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ, मीडिया, स्थानीय विकास, महिला सशक्तिकरण तथा उम्मीदवार की विश्वसनीयता जैसे कारक भी उनके मतदान निर्णय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। निष्कर्षतः बिहार की महिलाएँ एक स्वतंत्र एवं निर्णायक मतदाता वर्ग के रूप में उभर रही हैं, जिससे लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व एवं प्रतिनिधित्व दोनों सुदृढ़ हो रहे हैं। प्रस्तुत अध्ययन महिलाओं की राजनीतिक साक्षरता, डिजिटल जागरूकता, नेतृत्व विकास तथा महिला-केंद्रित लोकतांत्रिक नीतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देता है, ताकि भारतीय लोकतंत्र को अधिक सहभागी, समावेशी एवं उत्तरदायी बनाया जा सके।

*Corresponding Author:
Email address: Aditya Raj (araj4677@gmail.com), Dr. Md. Jawed Anwar (anwarmdjawed77@gmail.com)

Received: 25 July 2026; **Accepted:** 20 August 2026; **Published:** 11 September 2026
DOI: 10.29121/ShodhSamajik.v3.i2.2026.149
Page Number: 147-154
Journal Title: ShodhSamajik: Journal of Social Studies
Journal Abbreviation: ShodhSamajik J. Soc. Stud.
Online ISSN: 3049-2319, **Print ISSN:** 3108-2009
Publisher: Granthaalayah Publications and Printers, India
Conflict of Interests: The authors declare that they have no competing interests.
Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.
Authors' Contributions: Each author made an equal contribution to the conception and design of the study. All authors have reviewed and approved the final version of the manuscript for publication.
Transparency: The authors affirm that this manuscript presents an honest, accurate, and transparent account of the study. All essential aspects have been included, and any deviations from the original study plan have been clearly explained. The writing process strictly adhered to established ethical standards.
Copyright: © 2026 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

Keywords: Women Voters, Voting Behavior, Bihar, Democracy, Political Participation, Election, महिला मतदाता, मतदान व्यवहार, बिहार, लोकतंत्र, राजनीतिक सहभागिता, निर्वाचन

प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने प्रत्येक नागरिक को शासन-निर्माण की प्रक्रिया में समान भागीदारी का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका केवल मतदाता के रूप में ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की संवाहक, सामाजिक परिवर्तन की वाहक तथा राजनीतिक निर्णयों की महत्वपूर्ण सहभागी के रूप में भी निरंतर सुदृढ़ हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में क्रमिक वृद्धि हुई है, किंतु पिछले दो दशकों में यह वृद्धि विशेष रूप से अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। निर्वाचन आयोग के आँकड़े यह संकेत करते हैं कि अनेक राज्यों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के बराबर अथवा उससे अधिक हो चुका है, जो भारतीय लोकतंत्र की समावेशी प्रकृति को सुदृढ़ करता है।

भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है। बिहार की राजनीतिक एवं सामाजिक संरचना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं से परिपूर्ण है। राज्य की राजनीति पर लंबे समय तक जाति, वर्ग, धर्म तथा पारिवारिक प्रभाव का वर्चस्व रहा है, किन्तु बदलते सामाजिक-आर्थिक परिवेश, शिक्षा के विस्तार, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं ने महिलाओं की राजनीतिक चेतना और सहभागिता को नई दिशा प्रदान की है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों, जीविका कार्यक्रम, शिक्षा के प्रसार तथा डिजिटल संचार माध्यमों ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक और सक्रिय बनाया है। परिणामस्वरूप, बिहार में महिला मतदाता अब केवल पारिवारिक निर्णयों का अनुसरण करने वाली इकाई न रहकर स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय लेने वाली महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में उभर रही हैं।

यद्यपि भारतीय चुनावों में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ी है, तथापि बिहार में महिलाओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले निर्धारक कारकों का समग्र एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित है। अधिकांश पूर्ववर्ती अध्ययन जाति, वर्ग या चुनावी परिणामों तक सीमित रहे हैं, जबकि महिलाओं के स्वतंत्र मतदान निर्णय, राजनीतिक जागरूकता, कल्याणकारी योजनाओं, स्थानीय विकास, मीडिया तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रभावों का समेकित विश्लेषण अपेक्षित है। यही इस अध्ययन की प्रमुख आवश्यकता एवं शोधगत औचित्य है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य बिहार में महिलाओं के मतदान व्यवहार के प्रमुख निर्धारक कारकों का बहुआयामी विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा संस्थागत कारकों की भूमिका का परीक्षण किया गया है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि बदलते लोकतांत्रिक परिदृश्य में महिला मतदाता किस प्रकार अपने मतदान निर्णय का निर्माण करती हैं। यह अध्ययन न केवल बिहार में महिला राजनीतिक सहभागिता को समझने में सहायक होगा, बल्कि महिला-केंद्रित लोकतांत्रिक नीतियों के निर्माण एवं निर्वाचन संबंधी भविष्य के शोधों के लिए भी उपयोगी आधार प्रदान करेगा।

बिहार में महिलाओं के मतदान का परिदृश्य

भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता निरंतर सुदृढ़ हुई है, किंतु बिहार इस परिवर्तन का विशेष उदाहरण प्रस्तुत करता है। पिछले डेढ़ दशक में राज्य में महिला मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। निर्वाचन आयोग के आँकड़े दर्शाते हैं कि जहाँ 2000 के दशक के प्रारम्भ तक महिला मतदान पुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत कम था, वहीं 2014 के बाद से महिलाओं की भागीदारी में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। कई चुनावों में महिला मतदान प्रतिशत पुरुषों के बराबर अथवा उससे अधिक रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बिहार की महिलाएँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक निर्णायक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी हैं।

तालिका 1

तालिका 1 बिहार विधानसभा चुनाव: पुरुष बनाम महिला मतदान प्रतिशत (2010 - 2020)

निर्वाचन वर्ष	पुरुष मतदान (%)	महिला मतदान (%)	मतदान अंतर (महिला - पुरुष)
2010	51.12%	54.49%	**+ 3.37%**
2015	53.32%	60.48%	**+ 7.16%**
2020	54.45%	59.69%	**+ 5.24%**

स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India), Statistical Reports on Bihar Legislative Assembly Elections, 2010, 2015 एवं 2020.

बिहार विधानसभा चुनावों के आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 में महिला मतदान प्रतिशत 54.49% था, जबकि पुरुष मतदान 51.12% दर्ज किया गया। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदान बढ़कर 60.48% तथा पुरुष मतदान 53.32% रहा। इसी प्रकार वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदान 59.69% तथा पुरुष मतदान 54.45% दर्ज किया गया। ये आँकड़े संकेत करते हैं कि पिछले तीन विधानसभा चुनावों में महिलाओं की मतदान सहभागिता लगातार पुरुषों से अधिक रही, जो राज्य में महिला राजनीतिक जागरूकता, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, पंचायत स्तर पर आरक्षण तथा सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण परिणाम माना जा सकता है।

तालिका 2

तालिका 2 बिहार में लोकसभा चुनाव: पुरुष बनाम महिला मतदान प्रवृत्तियाँ (2014 - 2024)

लोकसभा चुनाव वर्ष	पुरुष मतदान (%)	महिला मतदान (%)	अंतर (महिला - पुरुष)
2014	54.95%	57.70%	**+ 2.75%**
2019	54.90%	59.58%	**+ 4.68%**
2024	53.00%	59.45%	**+ 6.45%**

स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India), लोकसभा चुनाव सांख्यिकीय प्रतिवेदन (Statistical Reports on General Elections to Lok Sabha), 2014, 2019 एवं 2024.

लोकसभा चुनावों में भी बिहार की महिला मतदाताओं की सक्रियता उल्लेखनीय रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार वर्ष 2014 के आम चुनाव में महिला मतदान 57.70% था, जबकि पुरुष मतदान 54.95% रहा। वर्ष 2019 में महिला मतदान बढ़कर 59.58% हो गया, जबकि पुरुष मतदान 54.90% दर्ज किया गया। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला मतदान 59.45% तथा पुरुष मतदान 53.00% रहा। इन आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय स्तर के चुनावों में भी बिहार की महिलाओं ने निरंतर उच्च मतदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भूमिका को सुदृढ़ किया है।

पुरुष एवं महिला मतदान प्रतिशत की तुलना से यह निष्कर्ष निकलता है कि बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अब केवल प्रतीकात्मक नहीं रह गई है। पूर्व में यह धारणा प्रचलित थी कि महिलाओं का मतदान मुख्यतः परिवार अथवा पुरुष सदस्यों के राजनीतिक निर्णयों से प्रभावित होता है, किन्तु वर्तमान चुनावी प्रवृत्तियाँ दर्शाती हैं कि महिलाएँ शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय विकास, कल्याणकारी योजनाओं, महँगाई, रोजगार, स्वास्थ्य तथा उम्मीदवार की विश्वसनीयता जैसे मुद्दों के आधार पर अपेक्षाकृत स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय लेने लगी हैं। इस परिवर्तन ने बिहार की चुनावी राजनीति में महिला मतदाताओं को एक निर्णायक मतदाता वर्ग के रूप में स्थापित किया है।[4]

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की तुलना करने पर यह पाया गया है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की मतदान भागीदारी सामान्यतः अधिक रहती है, जबकि प्रमुख शहरी क्षेत्रों—विशेषकर पटना जैसे नगरों में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम देखा गया है। इसके पीछे प्रवासन, शहरी उदासीनता, मतदाता सूची से संबंधित समस्याएँ तथा चुनाव के प्रति अपेक्षाकृत कम नागरिक सहभागिता जैसे कारण माने जाते हैं। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों (SHGs), जीविका कार्यक्रम, स्थानीय नेतृत्व तथा निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता अभियानों ने महिलाओं की चुनावी भागीदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है।

महिलाओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक

सामाजिक कारक

महिलाओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले निर्धारक कारकों में सामाजिक कारकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय समाज की सामाजिक संरचना, विशेषकर बिहार जैसे राज्य में, जाति, धर्म, परिवार, पितृसत्तात्मक व्यवस्था तथा सामाजिक मान्यताओं से गहराई से प्रभावित रही है। यद्यपि शिक्षा, शहरीकरण तथा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों ने महिलाओं की राजनीतिक चेतना को व्यापक बनाया है, फिर भी सामाजिक संरचनाएँ उनके मतदान निर्णयों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।

जाति बिहार की राजनीति का एक प्रमुख सामाजिक आधार रही है। लंबे समय तक विभिन्न राजनीतिक दलों ने जातीय समीकरणों के आधार पर चुनावी रणनीतियाँ तैयार कीं, जिसका प्रभाव महिला मतदाताओं पर भी पड़ा। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान निर्णय पारिवारिक अथवा जातीय समूह की सामूहिक राजनीतिक प्राथमिकताओं से प्रभावित होता रहा है। तथापि, हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे परिवर्तित हो रही है तथा महिलाएँ उम्मीदवार की कार्यक्षमता, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं को भी मतदान का आधार बनाने लगी हैं।

धर्म भी महिलाओं के मतदान व्यवहार का एक महत्वपूर्ण सामाजिक निर्धारक है। धार्मिक पहचान, सामुदायिक नेतृत्व तथा सांस्कृतिक परंपराएँ कई बार मतदाताओं की राजनीतिक प्राथमिकताओं को प्रभावित करती हैं। हालांकि लोकतांत्रिक जागरूकता तथा शिक्षा के विस्तार के कारण धार्मिक प्रभाव की प्रकृति में परिवर्तन आया है और महिलाएँ केवल धार्मिक अपील के आधार पर मतदान करने के बजाय विकास, सुरक्षा तथा सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों को भी महत्व देने लगी हैं।

परिवार भारतीय समाज की सबसे प्रभावशाली सामाजिक संस्था है। विशेष रूप से ग्रामीण बिहार में लंबे समय तक महिलाओं के मतदान संबंधी निर्णय परिवार के वरिष्ठ सदस्यों अथवा पति की राजनीतिक प्राथमिकताओं से प्रभावित होते रहे हैं। किन्तु शिक्षा के प्रसार, आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वयं सहायता समूहों, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी तथा मीडिया की बढ़ती पहुँच ने महिलाओं में स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता को विकसित किया है। परिणामस्वरूप परिवार का प्रभाव अब भी विद्यमान है, किन्तु उसका स्वरूप पहले की अपेक्षा अधिक परामर्शात्मक होता जा रहा है। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिक नियंत्रण, लैंगिक असमानता तथा निर्णय-निर्माण की सीमित स्वतंत्रता ने लंबे समय तक महिलाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया। किन्तु महिला शिक्षा, संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण नीतियों तथा सरकारी सशक्तिकरण कार्यक्रमों ने इस स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। आज बिहार की महिलाएँ अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति अधिक सजग हैं तथा मतदान को लोकतांत्रिक अधिकार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार कर रही हैं।

आर्थिक कारक

महिलाओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्धारकों में आर्थिक कारकों का विशेष महत्व है। आर्थिक स्थिति न केवल मतदाताओं की राजनीतिक प्राथमिकताओं को प्रभावित करती है, बल्कि शासन के प्रति उनकी अपेक्षाओं, सार्वजनिक नीतियों के मूल्यांकन तथा मतदान संबंधी निर्णयों को भी दिशा प्रदान करती है। बिहार जैसे विकासशील राज्य में आय, रोजगार, गरीबी, स्वरोजगार तथा स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियाँ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एवं मतदान व्यवहार पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं।

आय का स्तर महिलाओं के मतदान व्यवहार का एक महत्वपूर्ण आर्थिक निर्धारक है। निम्न आय वर्ग की महिलाएँ प्रायः उन राजनीतिक दलों अथवा प्रत्याशियों को प्राथमिकता देती हैं, जिनकी नीतियाँ सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आवास, शिक्षा तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) जैसी योजनाओं पर केंद्रित होती हैं। इसके विपरीत अपेक्षाकृत उच्च आय वर्ग की महिलाएँ रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना, आर्थिक विकास तथा सुशासन जैसे मुद्दों को अधिक महत्व देती हैं। इस प्रकार आय का स्तर मतदान की प्राथमिकताओं को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है।

रोजगार की उपलब्धता भी महिलाओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। जिन क्षेत्रों में महिलाओं को स्वरोजगार, कृषि, लघु उद्योग अथवा सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, वहाँ उनकी राजनीतिक जागरूकता तथा स्वतंत्र मतदान की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाएँ स्थानीय विकास, रोजगार सृजन तथा महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों के आधार पर अधिक विवेकपूर्ण मतदान निर्णय लेती हैं।

गरीबी भी मतदान व्यवहार का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। बिहार में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनेक परिवारों की महिलाएँ सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं, जैसे- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इन योजनाओं की प्रभावशीलता उनके मतदान निर्णय को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों में सम्मिलित होती है।

स्वरोजगार एवं महिला उद्यमिता ने भी महिलाओं की राजनीतिक चेतना को सुदृढ़ किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों तथा बिहार के 'जीविका' कार्यक्रम ने लाखों ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के परिणामस्वरूप महिलाओं में आत्मविश्वास, सामाजिक भागीदारी तथा स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है। जीविका समूहों के माध्यम से वित्तीय समावेशन, बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच तथा सामुदायिक नेतृत्व के अवसर बढ़ने से महिलाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

राजनीतिक कारक

महिलाओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले निर्धारक कारकों में राजनीतिक कारकों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता का निर्णय केवल सामाजिक अथवा आर्थिक परिस्थितियों से ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि राजनीतिक दलों की नीतियाँ, चुनावी अभियान, प्रत्याशी की छवि, नेतृत्व, दलगत पहचान तथा महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से भी गहराई से जुड़ा होता है। बिहार की राजनीति में पिछले दो दशकों के दौरान महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी ने राजनीतिक दलों को महिला-केंद्रित नीतियों, कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा चुनावी रणनीतियों पर विशेष बल देने के लिए प्रेरित किया है।

राजनीतिक दल महिलाओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख अभिकर्ता हैं। प्रत्येक दल अपने चुनावी घोषणा-पत्र, वैचारिक दृष्टिकोण तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से महिला मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करता है। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित वादे महिलाओं के मतदान निर्णय को प्रभावित करने वाले प्रमुख राजनीतिक मुद्दे बन चुके हैं। इससे स्पष्ट होता है कि महिला मतदाता अब केवल पारंपरिक सामाजिक पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि नीतिगत विकल्पों के आधार पर भी मतदान करने लगी हैं।

चुनाव प्रचार भी मतदान व्यवहार का महत्वपूर्ण निर्धारक है। जनसभाएँ, पदयात्राएँ, घर-घर संपर्क अभियान, महिला सम्मेलन, नुक्कड़ सभाएँ तथा डिजिटल प्रचार माध्यम मतदाताओं तक राजनीतिक संदेश पहुँचाने के प्रमुख साधन हैं। विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय महिला नेतृत्व तथा सामुदायिक संगठनों के माध्यम से संचालित चुनावी अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। हाल के वर्षों में राजनीतिक दलों ने महिलाओं को लक्षित करते हुए अलग-अलग चुनावी घोषणाएँ एवं कल्याणकारी वादे प्रस्तुत किए हैं, जिनका उनके मतदान निर्णय पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखा गया है।

उम्मीदवार की छवि भी महिलाओं के मतदान व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्याशी की ईमानदारी, सामाजिक प्रतिष्ठा, जनसंपर्क, विकास कार्यों का रिकॉर्ड, सुगम उपलब्धता तथा महिला सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति उसका दृष्टिकोण महिला मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण मानदंड बनते जा रहे हैं। विशेष रूप से स्थानीय निकायों तथा विधानसभा चुनावों में मतदाता प्रत्याशी की व्यक्तिगत विश्वसनीयता एवं क्षेत्रीय विकास के प्रति उसकी सक्रियता का मूल्यांकन करके अपने मतदान का निर्णय लेते हैं।

महिला आरक्षण ने भी महिलाओं की राजनीतिक चेतना को सुदृढ़ किया है। पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए मिले आरक्षण ने लाखों महिलाओं को नेतृत्व एवं राजनीतिक निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ा है। इससे महिला मतदाताओं में राजनीतिक आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता तथा लोकतांत्रिक सहभागिता का विस्तार हुआ है। इसके अतिरिक्त संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित विमर्श ने भी महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया है।

पार्टी पहचान तथा नेतृत्व भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण राजनीतिक कारक हैं। अनेक महिला मतदाता किसी राजनीतिक दल के साथ दीर्घकालिक वैचारिक अथवा भावनात्मक जुड़ाव के आधार पर मतदान करती हैं, जबकि दूसरी ओर करिश्माई नेतृत्व, सुशासन, विकास तथा जनविश्वास भी उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं। बिहार की राजनीति में नेतृत्व की विश्वसनीयता, प्रशासनिक दक्षता तथा जनकल्याणकारी नीतियों के प्रभाव ने महिला मतदाताओं के राजनीतिक व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए है।

सरकारी योजनाओं का प्रभाव

विगत एक दशक में केंद्र एवं बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं ने महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ उनके मतदान व्यवहार को भी उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है। लोकतांत्रिक राजनीति में कल्याणकारी योजनाएँ (Welfare Schemes) केवल विकास के साधन नहीं हैं, बल्कि वे सरकार एवं नागरिकों के मध्य विश्वास निर्माण का भी महत्वपूर्ण माध्यम बनती हैं। विशेष रूप से महिलाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी योजनाओं का प्रभाव उनके राजनीतिक दृष्टिकोण तथा मतदान संबंधी निर्णयों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने से घरेलू जीवन, स्वास्थ्य तथा समय की बचत में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आए इस परिवर्तन ने सरकार के प्रति सकारात्मक धारणा विकसित करने में योगदान दिया है। इसी प्रकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की पहल ने महिलाओं के दैनिक श्रम को कम किया तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाया है। इन योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं में शासन के प्रति विश्वास तथा राजनीतिक सहभागिता की भावना अपेक्षाकृत अधिक देखी गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने गरीब एवं वंचित परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराकर महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मान की भावना को सुदृढ़ किया है। अनेक राज्यों में आवास का स्वामित्व महिलाओं के नाम अथवा संयुक्त नाम से दिए जाने की व्यवस्था ने उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाया है। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से बैंक खाते, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है, जिससे महिलाएँ पहली बार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बड़े पैमाने पर जुड़ीं हैं।

बिहार में जीविका (Bihar Rural Livelihoods Promotion Society) कार्यक्रम ने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार, बचत, ऋण सुविधा तथा सामुदायिक नेतृत्व के अवसर प्रदान किए हैं। इससे महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक आत्मविश्वास तथा राजनीतिक जागरूकता का विस्तार हुआ है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना ने बालिकाओं की विद्यालयी उपस्थिति एवं माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच में वृद्धि कर महिला शिक्षा और दीर्घकालीन राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इसी प्रकार, समेकित बाल विकास सेवा (ICDS), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN) तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी पोषण योजनाओं ने महिलाओं एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य, पोषण तथा मानव विकास को सुदृढ़ किया है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकारी संस्थाओं के साथ महिलाओं का प्रत्यक्ष संपर्क बढ़ा है, जिससे शासन के प्रति उनकी जागरूकता एवं लोकतांत्रिक सहभागिता में वृद्धि हुई है। तथापि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि मतदान व्यवहार केवल योजनाओं के लाभ तक सीमित नहीं होता, बल्कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, लाभार्थियों की संतुष्टि तथा स्थानीय प्रशासन की कार्यकुशलता भी महिलाओं के राजनीतिक निर्णय को समान रूप से प्रभावित करती है।

तालिका 3

तालिका 3 महिलाओं के मतदान व्यवहार पर प्रमुख सरकारी योजनाओं का प्रभाव

सरकारी योजना	महिलाओं पर प्रमुख प्रभाव	मतदान व्यवहार पर संभावित प्रभाव
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	स्वच्छ ईंधन, स्वास्थ्य एवं समय की बचत	सरकार के प्रति सकारात्मक धारणा
जल जीवन मिशन	घर-घर पेयजल, श्रम में कमी	विकास एवं आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता
प्रधानमंत्री आवास योजना	सुरक्षित आवास एवं सामाजिक सम्मान	कल्याणकारी नीतियों के प्रति समर्थन
प्रधानमंत्री जनधन योजना	वित्तीय समावेशन एवं DBT	आर्थिक सुरक्षा एवं सरकारी विश्वास
जीविका (SHGs)	स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता एवं नेतृत्व	स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय एवं सहभागिता
मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना	बालिका शिक्षा एवं विद्यालयी उपस्थिति	दीर्घकालीन राजनीतिक जागरूकता
पोषण योजनाएँ (ICDS/PM POSHAN)	स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार	जनकल्याणकारी नीतियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण

स्रोत: विभिन्न सरकारी मंत्रालयों एवं विभागों की आधिकारिक रिपोर्टें (PMUY, JJM, PMAY-G, PMJDY, ICDS, PM POSHAN, BRLPS, बिहार सरकार)।

मीडिया एवं सोशल मीडिया का प्रभाव

समकालीन लोकतांत्रिक राजनीति में मीडिया एवं सोशल मीडिया महिलाओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण संचार माध्यमों के रूप में उभरे हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने राजनीतिक दलों, निर्वाचन आयोग तथा नागरिक समाज को मतदाताओं तक शीघ्र एवं व्यापक रूप से पहुँचने का अवसर प्रदान किया है। बिहार में टेलीविजन, मोबाइल फोन तथा इंटरनेट की बढ़ती पहुँच ने महिला मतदाताओं की राजनीतिक जागरूकता एवं चुनावी भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

टेलीविजन आज भी ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में राजनीतिक सूचना का प्रमुख स्रोत है। समाचार चैनल, चुनावी बहस, नेताओं के साक्षात्कार तथा सरकारी योजनाओं से संबंधित कार्यक्रम महिलाओं को राजनीतिक घटनाक्रम से परिचित कराते हैं। चुनाव के दौरान प्रसारित चर्चाएँ एवं विश्लेषण मतदाताओं को विभिन्न दलों की नीतियों और प्रत्याशियों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करते हैं।

स्मार्टफोन एवं मोबाइल इंटरनेट के विस्तार ने राजनीतिक संचार की प्रकृति में व्यापक परिवर्तन किया है। **WhatsApp, Facebook** तथा **YouTube** जैसे डिजिटल मंच चुनावी प्रचार के प्रभावी माध्यम बन चुके हैं। राजनीतिक दल इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से घोषणापत्र, वीडियो संदेश, जनसभाओं का सीधा प्रसारण तथा महिला-केंद्रित योजनाओं की जानकारी प्रसारित करते हैं। इससे महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता तथा चुनावी सूचना तक पहुँच में वृद्धि हुई है।

हालाँकि सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभावों के साथ-साथ चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। फेक न्यूज़, दुष्प्रचार, भ्रामक वीडियो तथा अपुष्ट राजनीतिक संदेश मतदाताओं की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। अतः डिजिटल साक्षरता एवं तथ्य-जाँच (Fact-checking) की क्षमता महिलाओं के विवेकपूर्ण मतदान निर्णय के लिए अत्यंत आवश्यक है। निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित **SVEEP** कार्यक्रम तथा विभिन्न नागरिक जागरूकता अभियानों ने मतदाताओं को सत्यापित सूचना के महत्व के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है।

स्थानीय मुद्दे एवं विकास

महिलाओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में स्थानीय विकास संबंधी मुद्दों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता केवल राष्ट्रीय अथवा राज्यस्तरीय राजनीतिक विमर्श से ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि अपने दैनिक जीवन से जुड़े स्थानीय प्रश्नों के आधार पर भी मतदान निर्णय लेते हैं। बिहार में विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा तथा शराबबंदी जैसे विषय चुनावी प्राथमिकताओं के केंद्र में रहे हैं।

सड़क एवं परिवहन सुविधाओं के सुधार ने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, बाजार तथा रोजगार तक पहुँच को सरल बनाया है। इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तथा अस्पतालों की उपलब्धता महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है और यह चुनावी निर्णय का महत्वपूर्ण आधार बनती है।

शिक्षा एवं रोजगार के अवसर भी महिला मतदाताओं की प्रमुख अपेक्षाओं में सम्मिलित हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रम तथा स्थानीय रोजगार के अवसर महिलाओं एवं उनके परिवारों के सामाजिक-आर्थिक विकास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। इसलिए महिला मतदाता ऐसे प्रतिनिधियों को प्राथमिकता देती हैं जो स्थानीय विकास को बढ़ावा देने में सक्षम हों।

महिला सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था भी मतदान व्यवहार का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। सुरक्षित सार्वजनिक वातावरण, महिला हेल्पलाइन, पुलिस व्यवस्था तथा लैंगिक संवेदनशील प्रशासन महिलाओं के राजनीतिक विश्वास को सुदृढ़ करते हैं।

बिहार में शराबबंदी नीति महिलाओं के बीच एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे के रूप में उभरी है। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि शराबबंदी से घरेलू हिंसा में कमी आई है तथा पारिवारिक आय में वृद्धि हुई है, जिसका प्रभाव महिलाओं के मतदान व्यवहार में भी परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय विकास एवं जनजीवन से जुड़े मुद्दे महिलाओं के मतदान संबंधी निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नीतिगत सुझाव

महिलाओं के मतदान व्यवहार को अधिक स्वतंत्र, जागरूक एवं लोकतांत्रिक बनाने के लिए बहुआयामी नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता है। केवल मतदान प्रतिशत में वृद्धि लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का पर्याप्त संकेतक नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि महिलाएँ राजनीतिक मुद्दों, सार्वजनिक नीतियों तथा अपने संवैधानिक अधिकारों की समुचित समझ के आधार पर मतदान करें। इस दृष्टि से सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलों, स्थानीय निकायों तथा नागरिक समाज की समन्वित भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सर्वप्रथम, महिला राजनीतिक शिक्षा को विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सामुदायिक स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संविधान, निर्वाचन प्रक्रिया, मतदाता अधिकार एवं लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं की राजनीतिक साक्षरता को सुदृढ़ कर सकते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किए जाने चाहिए।

निर्वाचन आयोग को Systematic Voters' Education and Electoral Participation (SVEEP) कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाते हुए महिलाओं के लिए स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण, डिजिटल जागरूकता अभियान तथा तथ्य-आधारित चुनावी सूचना उपलब्ध करानी चाहिए। साथ ही चुनावी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी एवं महिला-अनुकूल बनाने के लिए मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।

राजनीतिक दलों को महिला मतदाताओं को केवल चुनावी लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि नीति-निर्माण के सक्रिय भागीदार के रूप में देखना चाहिए। दलों को टिकट वितरण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने तथा चुनावी घोषणापत्रों में महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित ठोस नीतियाँ सम्मिलित करनी चाहिए।

स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण भी महिला राजनीतिक सहभागिता के विस्तार का प्रभावी माध्यम है। पंचायतों एवं नगर निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशासनिक, वित्तीय एवं नेतृत्व संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे वे स्थानीय शासन में प्रभावी भूमिका निभा सकें तथा अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बनें।

इसके अतिरिक्त महिला नेतृत्व विकास हेतु नेतृत्व प्रशिक्षण, राजनीतिक संवाद, युवा महिला नेतृत्व कार्यक्रम तथा स्वयं सहायता समूहों (SHGs/जीविका) के माध्यम से नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व दोनों सुदृढ़ होंगे।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में महिलाओं का मतदान व्यवहार विगत दो दशकों में उल्लेखनीय रूप से परिवर्तित हुआ है। महिला मतदाता अब केवल पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं, जैसे जाति, धर्म अथवा पारिवारिक प्रभाव तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे शिक्षा, आर्थिक स्थिति, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, राजनीतिक नेतृत्व, मीडिया, स्थानीय विकास तथा डिजिटल सूचना जैसे अनेक कारकों के आधार पर अधिक स्वतंत्र एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने लगी हैं। निर्वाचन आयोग के आँकड़े भी यह दर्शाते हैं कि बिहार में महिलाओं की मतदान भागीदारी निरंतर बढ़ी है, जो लोकतांत्रिक परिपक्वता एवं राजनीतिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण संकेत है।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि महिला मतदान व्यवहार बहुआयामी प्रकृति का है। सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के साथ-साथ शिक्षा, राजनीतिक साक्षरता, डिजिटल जागरूकता तथा प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने वाली सरकारी योजनाओं ने महिलाओं की राजनीतिक चेतना को सुदृढ़ किया है। जीविका जैसे स्वयं सहायता समूह, महिला शिक्षा, डिजिटल संचार तथा स्थानीय विकास संबंधी मुद्दों ने महिलाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक सक्रिय एवं उत्तरदायी भागीदार बनाया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्याशी की विश्वसनीयता, राजनीतिक दलों की नीतियाँ तथा सुशासन की धारणा भी मतदान निर्णय को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरे हैं।

लोकतांत्रिक दृष्टि से यह अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि महिलाओं की सक्रिय एवं जागरूक राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र की गुणवत्ता, प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व तथा समावेशी शासन को सुदृढ़ करती है। इसलिए महिला राजनीतिक शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, स्थानीय नेतृत्व विकास तथा समावेशी सार्वजनिक नीतियों को प्रोत्साहित करना केवल महिला सशक्तिकरण का माध्यम नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को अधिक सहभागी, उत्तरदायी एवं सुदृढ़ बनाने की एक अनिवार्य प्रक्रिया है।

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

Association for Democratic Reforms. (2014). Lok Sabha 2014: ADR-Daksh Survey Report for Bihar Region. Association for Democratic Reforms. (लोकसभा 2014: बिहार क्षेत्र के लिए ADR-दक्ष सर्वेक्षण रिपोर्ट। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स।)

Chhibber, P. K., and Verma, R. (2019). Ideology and Identity: The Changing Party Systems of India. Oxford University Press. (विचारधारा और पहचान: भारत की बदलती पार्टी प्रणालियाँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।)https://doi.org/10.1093/oso/9780190623876.001.0001

Deshpande, R., Tillin, L., and Kailash, K. K. (2019). The BJP's Welfare Schemes: Did they Make A Difference in the 2019 Elections? Studies in Indian Politics, (भाजपा की कल्याणकारी योजनाएँ: क्या उन्होंने 2019 के चुनावों में कोई अंतर पैदा किया? स्टडीज़ इन इंडियन पॉलिटिक्स) 7(2), 219–233. https://doi.org/10.1177/2321023019874911

Election Commission of India. (2010, 2015, 2020). Statistical Reports on General Elections to the Legislative Assembly of Bihar. Election Commission of India. (बिहार विधान सभा के आम चुनावों पर सांख्यिकीय रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग।)

Election Commission of India. (2024). Voter Education: Systematic Voters' Education and Electoral Participation (SVEEP). Election Commission of India. (मतदाता शिक्षा: व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (SVEEP)। भारत निर्वाचन आयोग।)

Election Commission of India. (2025). Bihar: Gender-Wise Poll Participation in Lok Sabha Elections (2014, 2019 and 2024). Election Commission of India. (बिहार: लोकसभा चुनावों (2014, 2019 और 2024) में लिंग-वार मतदान भागीदारी। भारत निर्वाचन आयोग।)

Kumar, S. (2013). Changing Electoral Politics in India: A Study of Women Voters. SAGE Publications. (भारत में बदलती चुनावी राजनीति: महिला मतदाताओं का एक अध्ययन। SAGE पब्लिकेशन्स।)

Kumar, S. (2022). Women Voters in Indian Elections: Changing Trends and Emerging Patterns. Routledge. (भारतीय चुनावों में महिला मतदाता: बदलते रुझान और उभरते पैटर्न। रूटलेज) https://doi.org/10.4324/9781003094432

Kumar, S., and Gupta, P. (2015). Changing Patterns of Women's Turnout in Indian Elections. Studies in Indian Politics, (भारतीय चुनावों में महिलाओं की मतदान भागीदारी के बदलते पैटर्न। स्टडीज़ इन इंडियन पॉलिटिक्स) 3(1), 1–15. https://doi.org/10.1177/2321023015575210

Pandey, R. K. (2026). Alcohol Ban and Populist Policies: New Dimensions of Women's Politics in Bihar. ShodhSamajik: Journal of Social Studies, (शराब पर प्रतिबंध और लोकलुभावन नीतियां: बिहार में महिला राजनीति के नए आयाम। शोधसामाजिक: जर्नल ऑफ़ सोशल स्टडीज़) 3(1), 32–39. https://doi.org/10.29121/ShodhSamajik.v3.i1.2026.72

Prabhuraj, J. (2025). A Study on the Influence of External Factors on Consumer Decision Making in the Digital Era. International Journal of Engineering Technologies and Management Research, (डिजिटल युग में ग्राहकों के फ़ैसला लेने की प्रक्रिया पर बाहरी कारकों के प्रभाव का अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड मैनेजमेंट रिसर्च) 12(4SE), 48–55. https://doi.org/10.29121/ijetmr.v12.i4SE.2025

Wiyanti, D. S., and Laksono, T. D. (2026). Analysis of Factors That Influence Consumers' Choices of Housing in Purbalingga Regency. International Journal of Engineering Technologies and Management Research, (पुरबालिंगा रीजेंसी में ग्राहकों की आवास पसंद को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड मैनेजमेंट रिसर्च) 13(1), 19–24. https://doi.org/10.29121/ijetmr.v13.i1.2026

Yadav, Y. (1999). The Second Rise of Indian Democracy: Electoral Behavior and Social Change in the 1990s. Time/Social Discussion, (भारतीय लोकतंत्र का दूसरा उदय: 1990 के दशक में चुनावी व्यवहार और सामाजिक परिवर्तन। टाइम/सोशल डिस्कशन) (4), 45–62.